

FROM :

FAX NO. :

Nov. 28 2005 04:03AM P1

झारखण्ड सरकार,
कार्यिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-:: अधिसूचना ::-

रांची, दिनांक-// नवम्बर, 2005

3890

संख्या-गवि/प्र०-०३-९७/२००५ का ०...../ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
दर्शकों की २२) की धारा २१ की उपचारा (२) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
उपयोग करते हुए झारखण्ड सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :-

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड सूचना का अधिकार (फीस और लागत का
विनियम) नियम, 2005 है।

(२) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(३) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी होगा।

२. परिमाण - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम की धारा अधिप्रेत है;

(ग) अन्य सभी शब्दों और पर्दों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं,
वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

३. धारा ६ की उप धारा (१) के अधीन सूचना अधिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, दस^{रुपए} का अल्लेज कॉस्ट के साथ होगा, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या
मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन
हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को संदेश होगा, प्रभारित की जाएगी।

४. धारा ७ की उप धारा (१) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस,
निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट
या बैंकर चेक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत
पदाधिकारी को संदेश होगा, प्रभारित की जाएगी ; -

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए ग्रन्थेक (ए-२ या ए-३ आकार)
कागज के लिए दो रुपए;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत
कोमल;

(ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और

2

- (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, यहसे घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पांच रुपए की फीस।
5. धारा 7 की उप धारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी को संदेश होगा, प्रभारित की जाएगी :-
- (क) डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति डिस्केट या फ्लॉपी, पचास रुपए; और
- (ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना को लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रुपए।

जारखंड सत्यापाल के व्यापेश में

(मुख्यमान सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

शापांक-7/विभिन्न-03-97/2005 का 3890 रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

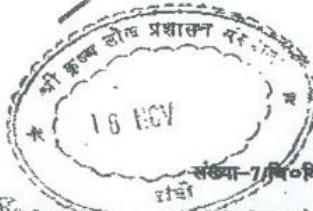
प्रतिलिपि- जारखंड सचिवालय मुद्रणालय, लेराप्पड, रांची को जारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 प्रतिशत इस विभाग को उपलब्ध करावे की कृपा की जाए।

सरकार के प्रधान सचिव।

शापांक-7/विभिन्न-03-97/2005 का 3890 रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी निगम/निकाय/उपक्रम/गैर सरकारी संस्थाएं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।



झारखण्ड सरकार,
कार्यपालिका, प्रशासनिक सुचना तथा राजभाषा विभाग।

-::: अधिकृत सूचना ::-

रांची, दिनांक- / 4 नवम्बर, 2005

3869

संख्या-7/विधि/सं-0-03-97/2005 का..... सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (इ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
झारखण्ड सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रकाश -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड सूचना का अधिकार (अपील की विधि) नियम, 2005 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।
- (3) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी होगा।

2. परिभाषा -

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;
- (ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ग) "आयोग" से झारखण्ड सूचना आयोग अभिप्रेत है;
- (घ) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभ्रंशित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. अपील दायर करने की प्रक्रिया :-

अपील दायर करते समय अपीलकर्ता द्वारा आयोग को निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध करानी होती हैं :-

- (क) अपीलकर्ता का नाम और पता;
- (ख) लोक सूचना पदाधिकारी का नाम और पता;
- (ग) लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा पारित जिस आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया जा रहा हो की संख्या एवं सिद्धि सहित विवरणी;
- (घ) अपील हेतु संक्षिप्त तथ्य;
- (ङ) प्रार्थना या दावा किया गया अनुत्तोष;

- (च) प्रार्थना या अनुतोष का आधार;
- (छ) अधिनियम अथवा नियम के प्रावधान;
- (ज) अपीलकर्ता द्वारा स्तूपण; और
- (झ) अन्य कोई सूचनाएँ जो आयोग के अपील निर्धारण हेतु आवश्यक हों।

4. अपील के सभी प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात :-

आयोग के समक्ष दायर किये जाने वाले प्रत्येक अपील हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित कागजात प्रस्तुत करना होगा :-

- (क) उस आदेश की अभिप्रामाणित सच्ची प्रति जिसके विरुद्ध अपील किया जा रहा है;
- (ख) उन कागजातों की प्रति जिनके उल्लेख के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा अपील दायर किया जा रहा है; और
- (ग) उन कागजातों की अनुक्रमणिका, जो अपील में उल्लिखित हो।

5. अपील निष्पादन की विधि :-

अपील के निष्पादन में आयोग द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

- (क) संबंधित अथवा हितवद्ध व्यक्ति से शपथ पर भौतिक सुनवाई अथवा प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से लिखित समझ प्राप्त करेगा।
- (ख) इससे संबंधित कागजातों, लोक अभिलेखों अथवा इनके प्रतियों का अवलोकन अथवा निरीक्षण करेगा।
- (ग) प्राक्षिकृत पदाधिकारी के माध्यम से विवरणियों अथवा तथ्यों की जांच करायेगा।
- (घ) लोक सूचना पदाधिकारी, सहायक लोक सूचना पदाधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकार की यथास्थिति सुनवाई करेगा।
- (इ) तीसरे पक्ष की सुनवाई करेगा, तथा
- (च) लोक सूचना पदाधिकारी, सहायक लोक सूचना पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार अथवा तीसरे पक्ष से यथास्थिति प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से समझ प्राप्त करेगा।

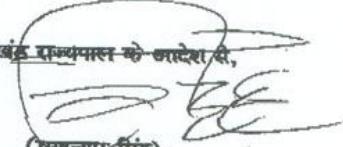
6. आयोग द्वारा नोटिस तामिला की प्रक्रिया :-

आयोग द्वारा निर्गत नोटिस को निम्नांकित माध्यम से तामिला कराया जा सकता है :-

- (क) पक्षकार द्वारा अपने स्तर से तामिला कराना
- (ख) प्रोसेस पिउन के माध्यम से (दस्ती) हाथों-हाथ तामिला कराना
- (ग) पावती के साथ निर्बोधित ड्राक द्वारा, अथवा
- (घ) कार्यालय प्रधान अथवा विभाग के माध्यम से ।

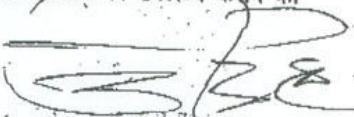
7. आदेश पर इस्तावत : -

आयोग द्वारा खुले कार्यवाही में दिया गया आदेश लिखित होगा तथा यह आयोग द्वारा इस हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होगा ।


 झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
 (भूपेन्द्र सिंह),
 सरकार के प्रधान सचिव ।

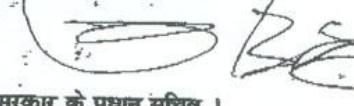
शापांक-7/विधि०विधि०सं०-03-97/2005 का०.....3889.....रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- झारखण्ड सचिवालय मुद्रणालय, डोरणडा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 200 प्रतियाँ इस विधानी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।


 सरकार के प्रधान सचिव ।

शापांक-7/विधि०विधि०सं०-03-97/2005 का०.....3889.....रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी निगम/ निकाय/ उपक्रम/ गैर सरकारी संस्थाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाही हेतु प्रेषित ।


 सरकार के प्रधान सचिव ।